Statement

Statement regarding Indigenisation in IAF

In early October, 1988 the then C.A.S. had given an interview to a correspondent of the Times of India who subsequently published an Article in the 8th October, 1988 edition of the Times of India as a special feature on the Air Force Day. In a recent Article published in the 16th August, 1991 issue of the Times of India, the author seems to have quoted para 1 of the Article published in October, 88. It appears that the Air Chief Marshal S. K. Mehra (Retd.) has been quoted out of the context with regard to his interview in 1988.

Indigenisation of defence equipments including those of Indian Air Force is an on-going exercise. Steps being taken by the Government to accelerate the pace of indigenisation in defence projects include the following :—

(i) The capacity available in the civil sector is being increasingly utilised to widen the base of indigenous production.

(ii) The Defence Production Units have time-bound targets for reducing import content in equipments produced by them and their performanec in this regard is being monitored in the Ministry.

(iii) Task Groups have been set up for identification and quantification of spares for maintenance/overhaul of a number of defence equipments in order to formulate time-bound plan for indigenisation of spares.

As a result of various steps taken for accelerating the pace of indigenisation in defence projects, there is a greater degree of self-reliance and lesser dependence on imports in respect of items which are indigenised.

Delay in acquisition of Advance Jet Trainer

571. KUMARI ALIA:
SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to take a decision on acquisition of the Advanced Jet Trainer for the Air Force; if so, by when the decision is likely to be taken;

(b) what are the reasons for the delay, if any, in taking the decision;

(c) what is the fate of the Advance Jet Trainer Project of Hindustan Aeronautics Limited;

(d) what are the reasons for the project not taking off in time ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) and (b) In view of the large investments involved in the acquisition it is necessary to closely examine the comparative techno-economic vailibility of all available options. Process is underway to arrive at an acceptable solution, keeping in view the resource availability and the interests of the Air Force and our production agencies.

(c) and (d) There is no proposal for HAL to develop an Advanced Jet Trainer.

Opening of Defence Production to Private Sector

572. KUMARI ALIA.
SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Government proposes to open up some areas of Defence production to the private sector; if so, whether Government proposes to allow Priavte Entrepreneurs to use surplus production capacity available with certain ordnance factories; and

(b) if so, what are Government's plans in this regard ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) and (b) In order to achieve a high degree of self reliance, Government's policy is to make optimum use of the national industrial infrastructure. Accordingly, capacities available in the civil sector both in the private and the

non-defence public sectors are being utilised for production of defence stores. There is no proposal to allow private entrepreneurs to make use of any capacity with the ordnance factories, except as buyers of products, for which opportunities are available even now.

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सी० एफ० टी० आर० आई० की एक शाखा का स्थापित किया जाना

573. श्रीमती रत्न कुमारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की एक शाखा मध्य प्रदेश में भोपाल या जबलपुर में स्थापित किए जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां। भोपाल या जबलपुर में सी०एफ०टी०आर० आई. का केन्द्र खोलने के अनुरोध के साथ मध्य प्रदेश सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य में फलों और अन्य खाद्य उत्पादों की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए मूलरूप से इन प्रस्तावों में एक सी०एफ टी०आर०आई० केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

(ग) इन प्रस्तावों की जांच की गई और प्रस्तावित नया केन्द्र निम्नांकित कारणों से न खोले जाने का निर्णय लिया गया :

(i) नागपुर में सी.एफ.टी.आर. आई. का एक केन्द्र है जो मध्य प्रदेश के छ भागों सहित देश के मध्य भाग (केन्द्रीय क्षेत्र) की विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करता है।

(ii) मध्य प्रदेश राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन (उपयोग) में विशेष रूप से सहायता प्रदान करने के लिए भोपाल में सी०एस०आई०आर० की पूर्ण सुसज्जित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है।

(iii) वर्ष 1989 में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली सी.एस.आई.आर. सोसाइटी ने यह निर्णय लिया था कि कोई भी नया क्षेत्रीय केन्द्र नहीं खोला जाना चाहिए और जो केन्द्र पहले से ही चल रहे हैं, उन्हें ही अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लगाया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश में उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर

574. **श्रीमती रत्न कुमारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या तक दूरदर्शन के कार्यक्रम पहुंच रहे हैं और जनसंख्या के अनुसारण अन्य राज्यों में दूरदर्शन कार्यक्रम देखने वालों की तुलना में इसका अनुपात कितना है ;

(ख) क्या सरकार मध्य प्रदेश में कोई और प्रभावशाली टी०वी० टावर अथवा एक उच्च शक्ति वाला टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि दूरदर्शन के कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोगों पर पहुंच सकें ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें मौजूदा दूरदर्शन नेटवर्क द्वारा कवर की गई प्रतिशत जनसंख्या का राज्य वार/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा दिया गया है।